



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102021-230280
CG-MH-E-09102021-230280

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]
No. 444]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 15 सितम्बर, 2021

सं. टीएएमपी/79/2015-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, दीनदयाल पत्तन न्यास की नमक-भूमि के मौजूदा दरमान की वैधता अवधि में, इसके साथ संलग्न आदेश अनुसार वृद्धि करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण मामला सं. टीएएमपी/79/2015-केपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

- (i). श्री. टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री. सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितम्बर 2021 के 15वें दिन पारित)

यह मामला, दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) की नमक भूमि के मौजूदा दरमान की वैधता अवधि में वृद्धि से संबंधित है।

2.1. कांडला में नमक भूमि के मौजूदा दरमान (एसओआर), पिछली बार प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/79/2015-केपीटी दिनांक 02 मई 2016 के तहत अनुमोदित किये गये थे जिन्हें भारत के राजपत्र में 26 मई 2016 को अधिसूचित किया गया था। इस आदेश में एसओआर की वैधता 04 जुलाई 2020 तक निर्धारित है।

2.2. इसके बाद, कांडला में नमक भूमि के एसओआर की वैधता अवधि में डीपीटी के अनुरोध पर, समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है। नमक भूमि के एसओआर की वैधता अवधि, पिछली बार आदेश संख्या टीएएमपी/79/2015-केपीटी दिनांक 16 मार्च 2021 के तहत 05 जनवरी 2021 से छह महीने के लिए अर्थात् 04 जुलाई 2021 तक या डीपीटी द्वारा दायर किए जाने वाले टैरिफ प्रस्ताव के आधार पर संशोधित लीज रेंटल की अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ायी गयी थी। उक्त आदेश में, डीपीटी से नमक भूमि के पट्टे के किराए के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव, 31 मई 2021 तक दाखिल करने का अनुरोध किया गया था।

2.3. अब, डीपीटी ने अपने दिनांक 22 जून 2021 के ईमेल के माध्यम से, अर्थात् 22 जून 2021 के संलग्न पत्र के अंतर्गत है, अनुरोध किया है कि डीपीटी ने भूमि प्रबंधन नीति दिशानिर्देश 2015 के प्रावधान 13(v) के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य का आकलन करने के लिए भूमि मूल्यांकनकर्ता को नियुक्त किया है। पत्तन ने कहा है कि मूल्यांकनकर्ता ने पूर्वावलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह पत्तन, अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी स्वीकृति के बाद, नमक भूमि की दर-संरचना में संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल करेगा और इसलिए संशोधित दरों को 05 जुलाई 2021 से प्रभावी होने के लिए अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा। इसलिए, डीपीटी ने मौजूदा एसओआर की वैधता को 04 जुलाई 2021 से आगे यानी 05 जुलाई 2021 से 04 जनवरी 2022 तक छह महीने की अवधि के लिए 2% की वृद्धि के साथ बढ़ाने का अनुरोध किया है।

3.1. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में और चूंकि कांडला में नमक भूमि के मौजूदा एसओआर की वैधता 04 जुलाई 2021 को समाप्त हो गई है और डीपीटी के अनुरोध के आधार पर, यह प्राधिकरण, कांडला में डीपीटी की नमक भूमि के मौजूदा एसओआर की वैधता अवधि 05 जुलाई 2021 से 04 जनवरी 2022 या संशोधित एसओआर के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने के लिए इच्छुक है। डीपीटी को 31 अक्टूबर 2021 से पहले नमक भूमि के लिए लीज किराया के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह दी जाती है।

3.2. इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी 2014 के संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देश, जिनके आधार पर डीपीटी की नमक भूमि के लिए दर संरचना इस प्राधिकरण द्वारा, मई 2016 में अनुमोदित की गई, यह निर्धारित है कि जब तक उसे प्राधिकरण द्वारा संशोधित नहीं किया जाता, तब तक इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराया में 2% प्रति वर्ष वृद्धि की जाएगी। इस प्राधिकरण द्वारा मई 2016 में अनुमोदित आदेश भी इस संबंध में भी यह विशिष्ट शर्त निर्धारित है। चूंकि मौजूदा दर संरचना में जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा दरों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संशोधित नहीं किया जाता है और पहले से ही पट्टा-किराया में 2% की दर से वार्षिक वृद्धि निर्धारित है, तथा डीपीटी द्वारा अनुरोध भी किया गया है, इसलिए, डीपीटी के कांडला में नमक भूमि के लिए दरमान संरचना की विस्तारित वैधता अवधि के दौरान 2% वार्षिक दर से वृद्धि जारी रखी जाएगी।

3.3. तथापि, इस संबंध में, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्तमान परिदृश्य में उत्पन्न एक शून्य से बचने के लिए केवल एक अस्थायी व्यवस्था है। इस संबंध में डीपीटी द्वारा दायर किए जाने वाले प्रस्ताव मौजूदा पट्टा किराया) लीज रेंटल (में 2% वार्षिक वृद्धि के साथ विस्तार, के आधार पर कांडला में नमक भूमि के लिए तय किए जाने वाले पट्टा किराया) लीज रेंटल (को डीपीटी के अनुरोध में यथापेक्षित, पूर्वव्यापी प्रभाव देना होगा।

4. परिणामतः और ऊपर दिए गए कारणों से, कांडला में दीनदयाल पत्तन न्यास की नमक भूमि की मौजूदा दर संरचना की वैधता अवधी, डीपीटी द्वारा दायर किए जाने वाले टैरिफ प्रस्ताव के आधार पर, इसकी समाप्ति की तारीख से अर्थात् 05 जुलाई 2021 से 04 जनवरी 2022 या प्रभावी होने की तारीख अथवा संशोधित लीज रेंटल की अधिसूचना होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाती है। डीपीटी को 31 अक्तूबर 2021 से पहले नमक भूमि के लिए लीज रेंट के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह दी जाती है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./303/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, 15th September, 2021

No. TAMP/79/2015-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of Salt Land of Deendayal Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/79/2015-KPT

Deendayal Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 15th day of September 2021)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of Salt Land of Deendayal Port Trust (DPT).

2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of Salt land at Kandla was last approved by the Authority vide Order No.TAMP/79/2015-KPT dated 02 May 2016 which was notified in the Gazette of India on 26 May 2016. The Order prescribed the validity of the SOR till 04 July 2020.

2.2. Subsequently, at the request of the DPT, the validity of the SOR of Salt land at Kandla was extended from time to time. The SOR of Salt land was last extended vide Order No.TAMP/79/2015-KPT dated 16 March 2021 for a period of six months from 05 January 2021 till 04 July 2021 or the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier. In the said Order, the DPT was requested to file its proposal for revision of lease rent of Salt land by 31 May 2021.

2.3. Now, the DPT has, vide its email dated 22 June 2021 under cover of which letter dated 22 June 2021 is attached, submitted that the DPT has appointed land valuer for assessing the market value of land as per provision 13(v) of Policy Guidelines for Land Management, 2015. The port has stated that the valuer has submitted the preview report and after receipt and acceptance of final report, the port will file the proposal for revision of rate structure of Salt land and therefore the finalization of revised rates applicable with effect from 05 July 2021 will take some time. Hence, DPT has requested to extend the validity of the existing SOR beyond 04 July 2021 i.e. for further period of six months from 05 July 2021 till 04 January 2022 with 2% escalation.

3.1. In view of the above and since the validity of the exiting SOR of Salt land at Kandla has expired on 04 July 2021 and based on the request made by the DPT, this Authority is inclined to extend the validity of the existing SOR of the Salt Lands at Kandla of the DPT from 05 July 2021 till 04 January 2022 or the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier. The DPT is advised to file its proposal for revision of lease rent for salt land before 31 October 2021.

3.2. Further, the revised Land Policy Guidelines of 2014 issued by the Government based on which the rate structure for Salt lands of DPT has been approved by this Authority in May 2016 stipulate that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by the Authority. The Order

approved by this Authority in May 2016 also prescribes a specific condition in this regard. Since the existing Rate structure already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till such time the rates are revised by this Authority and in line with the guidelines issued by the Government and as requested by the DPT, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the rate structure for Salt lands at Kandla of DPT.

3.3. However, in this regard, it is relevant to mention here that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the Salt lands at Kandla based on the proposal to be filed by the DPT in this regard shall have to be given retrospective effect, as requested by the DPT.

4. In the result, and for the reasons given above, the validity of the existing rate structure of Salt lands at Kandla of Deendayal Port Trust is extended from the date of its expiry i.e. from 05 July 2021 till 04 January 2022 or the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier. The DPT is advised to file its proposal for revision of lease rent for salt land before 31 October 2021.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./303/2021-22]